**पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा)** : (क) से (घ) 1994-95 के लिए तेल आयात बिल में वृद्धि/कमी अनेक घटकों पर आधारित होती है जैसे देशी उत्पादन की मात्रा विभिन्न रिफाइनरी विस्तार परियोजनाओं को पूरा करना, क्रूड और पेट्रोलियम उत्पादों की प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत, डालर की विद्यमान विनिमय साम्य आदि ।

गत तीन वर्षों के तेल आयात बिल निम्नानुसार है :—

| वर्ष | (करोड़ रुपए) |
|---|---|
| 1991-92* | 13038 |
| 1992-93* | 17045 |
| 1993-94* | 17730 |

*अनंतिम

(ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(च) पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में परिवर्तन केवल अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर आधारित नहीं है बल्कि अन्य घटकों जैसे घरेलू उत्पादन की प्रकृति इसकी लागत, और आयातित/निर्यात में परिवर्तन आदि पर भी निर्भर करते हैं ।

**रसोई गैस (एलपीजी) पर दी जाने वाली राज सहायता की राशि में वृद्धि**

1265. **श्री वीरेन जे. शाह :**
**श्री राम जेठमलानी :**

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित तेल कंपनियों को चालू वर्ष के दौरान 20 लाख नये रसोई गैस उपभोक्ताओं के नाम पंजीकृत करने के निर्देश दिए हैं जिससे उन्हें नये कनेक्शन दिए जा सकें ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने कुछ दिन पहले एलपीजी क्षेत्र में निजी क्षेत्र को कार्य करने की अनुमति दी थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि नये कनेक्शन जारी करने के बाद सरकार द्वारा दी जाने वाली राज-सहायता की राशि में वृद्धि होगी ;

(घ) यदि हां, तो इस राशि में 20 लाख कनेक्शन जारी होने के बाद कितनी वृद्धि हो जाने का अनुमान है और क्या सरकार इस राजसहायता को समाप्त करने या कम करने के लिए गैस सिलिंडरों के वर्तमान मूल्य में और वृद्धि करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस राजसहायता की राशि के कारण होने वाली हानि को क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या योजना है ?

**पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा)** : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) से (ङ) एलपीजी के वर्तमान मूल्यों पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन दिए जाने के परिणामस्वरूप राजसहायता में वृद्धि हो सकती है ।

**तेल क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश**

1266 **श्री राम गोपाल यादव : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी कम्पनियों को तेल के क्षेत्र में पूंजी निवेश करने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक उन कंपनियों ने कुल कितनी धनराशि का निवेश किया है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा)**: (क) और (ख) तेल की खोज, तेल क्षेत्र के विकास, रिफाइनरियों और ल्यूब के मिश्रण और विपणन तथा एलपीजी एस के ओ और अन्य अनियंत्रित मदों के समानान्तर विपणन तथा इसके लिए संबंध सुविधाओं में निवेशों की अनुमति दी जाती है।

(ग) ये परियोजनायें दीर्घ अवधि में पूरी होने वाली परियोजनायें हैं तथा निवेश चरणों में किए जाते हैं।

### रसोई गैस वैंडरों को हाथ से तोलने वाली मशीन का उपलब्ध कराया जाना

1267 श्री राम गोपाल यादव : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रसोई गैस उपभोक्ताओं से डीलरों द्वारा अक्सर कम भार के सिलिंडरों की आपूर्ति किये जाने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या रसोई गैस वैंडरों को उनके नियोक्ताओं द्वारा हाथ से तोलने वाली मशीनें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं जिससे शुद्ध-भार की पुष्टि कर उपभोक्ताओं को संतुष्ट किया जा सके ;

(घ) यदि हां, तो क्या उपभोक्ता संगठनों ने सरकार से कई बार रसोई गैस उपभोक्ताओं को सुविधा और संतुष्टि प्रदान करने की दृष्टि से रसोई गैस वितरकों द्वारा अपने वैंडरों को अनिवार्यतः हाथ से तोलने वाली मशीनें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा)**: (क) और (ख) एलपीजी की विपणन कर्त्ता कंपनियों ने बताया है कि 1993-94 के दौरान उनको ऐसी 14 संपुष्ट शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) सुपुर्दगीकर्त्ताओं को तोलने की हलकी मशीनें सप्लाई करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

(घ) और (ङ) यह सुझाव कि सुपुर्दगी कर्त्ता को अपने साथ तोलने की मशीन रखनी चाहिए और उपभोक्ता के समक्ष सिलिंडरों का वजन करना चाहिए विगत में प्रयोगिक आधार पर लागू किया गया था परन्तु यह कारगर सिद्ध नहीं हुआ।

### Hurdles in Introducing the Plan of lead-free petrol

1268. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the plan of the Ministry of Peroleum and Natural Gas to introduce lead-free petrol is facing hurdles.

(b) if so, the details thereof; and

(c) what final decision the Ministry has taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) to (c) Government have formulated a plan of lead phasing in petrol for metropolitan cities. According to the plan, by December 1994, petrol supply to metros (Bombay, Delhi, Calcutta and Madras) should have a maximum lead level of 0.15 gm/litre. The supply of low lead (015 gm/l max) M.S. to all four metropolitan cities has already commenced.

By December, 1997, Delhi and Bombay would be supplied with zero lead MS, whereas the rest of the country would have MS supplies of lead content not exceeding 0.15 gm/litre. However, it has been decided to introduce from April 1995, in a few selected retail outlets, supply of zero lead petrol in four metropolitan cities in order to cater to the requirement of the new vehicles which would be fitted with catalytic convertors.